**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2531**

**दिनांक 08 अगस्‍त, 2018**

**ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन के लिए लक्ष्य**

**2531. डा॰ सत्यनारायण जटियाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए वितरकों, वितरण नीति, कार्य योजना के लिए पांच वर्षों का राज्य- वार वार्षिक लक्ष्य क्या है; और

(ख) इस योजना के तहत कितने गरीब लोगों को अन्य रियायतों के साथ-साथ रियायती गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख): एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिपों की नियुक्‍ति एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिपों को स्‍थापित करने के लिए स्‍थलों की पहचान बिक्री संभाव्‍यता के आधार पर की जाती है जो उन्‍हें वाणिज्यिक रूप से व्‍यवहार्य बनाती है। एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिप स्‍थापित करने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्‍य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्तमान में 20585 एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर हैं। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने ‘एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिपों के चयन के लिए एकीकृत दिशा निर्देश’’ के तहत नई एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिपों के चयन हेतु 6351 स्‍थलों का विज्ञापन दिया है, जो अधिकांश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को स्‍वच्‍छ रसोई ईंधन उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की थी जिसके तहत प्रति कनेक्‍शन 1600 रुपए तक की नकद सहायता से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 8 करोड़ जमानत राशि मुक्‍त एलपीजी कनेक्‍शन प्रदान किए गए हैं। पीएमयूवाई के तहत, कोई लाभार्थी हॉट प्‍लेट (चूल्‍हा) अथवा पहली रीफिल अथवा दोनों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान कर सकता है अथवा उसके पास हॉट प्‍लेट अथवा पहली रीफिल अथवा दोनों को शून्‍य ब्‍याज दर पर ओएमसीज से ऋण आधार पर लेने का विकल्‍प है। दिनांक 03.08.2018 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्‍शन जारी किए गए हैं।

\*\*\*\*